

सम्पादकीय

दहेज कानून और पुरुष

कोई भी कानून समाज और पारिवारिक ताने-बाने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया जाता है, मगर जब उसका दुरुपयोग होने लगता है, तो वही कानून सामाजिक बुनियाद के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर देता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा कि दहेज कानून का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बेंगलुरु में नौकरी कर रहे बिहार के एक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला देशभर में गुंज रहा है।

अतुल सुभाष के विरुद्ध उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के प्रयास समेत नौ मामले दर्ज करवाए थे। दहेज प्रताड़ना के 2023 के पहले दोस्त मामले आईपीसी की धारा 498 के तहत चलाए जाते थे, भारतीय न्याय संहिता बन जाने के बाद अब दहेज प्रताड़ना के मामलों को धारा 85–86 के तहत दर्ज किया जाता है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए एक कलंक बन गई है। लड़का-लड़की दोनों ने एक दूसरे के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए इस कुप्रथा को मजबूत हथियार बना लिया है। हालांकि इस कानून का मूल उद्देश्य महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाना है और काफी हद तक इस कानून ने प्रभावशाली ढंग से काम किया और आज भी दहेज जैसी कुप्रथा के विरुद्ध असरदार बना हुआ है।

2015 और 2023 के बीच दहेज प्रताड़ना के करीब सवा लाख मामले गांवों से लेकर महानगरों में उच्चशिक्षित से लेकर अल्पशिक्षित परिवारों ने दर्ज करवाए। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाने के अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों ने सामाजिक संगठनों की मदद से व्यापक जन जागरूकता भी की, लेकिन समाज के बदलते स्वरूप, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत आकांक्षाओं के चलते परिवार में टक्कर भी बढ़ने लगे। इससे तमिल के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही दहेज प्रताड़ना के मामले भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस-अदालतों के सामने पहुंचने लगे।

बेंगलुरु की आईटी कंपनी में इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस ने दहेज कानून के लगातार बढ़ते दुरुपयोग की चर्चा को फिर उभार दिया है. पति-पत्नी और मायके-ससुराल वालों की अनबन के बीच दहेज अधिनियम की धारा 498ए एक हथियार बन गई है, जो एक को बनाए जाने के मकसद पर ही चोट कर रही है. दहेज उत्पीड़न के कई सालों से चल रहे केस में अपने और परिवार के मानसिक उत्पीड़न से अतुल सुभाष हार गए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 देश में एक मई 1961 को प्रभावी बनाया गया था. यह दहेज की कुप्रथा के खिलाफ रोक का पूरे देश में लागू करने का कानून था. इसके तहत दहेज प्रथा पर रोक और दहेज की वजह से लड़कियों के शोषण-उत्पीड़न पर रोक लगाना इसका उद्देश्य था। दहेज के लिए लड़कियों को भारने-पीटने, मार डालने या मानसिक उत्पीड़न जैसे मामलों को लेनेकर कानून लाया गया था. इसमें दहेज के लेनेदर को अपराध बनाया गया था. इस कानून में बार-बार संशोधन भी किया गया है।

इन सबके बीच दहेज कानून का सामना कर रहे लोगों की आत्महत्या के मामले भी सामने आने लगे। पिछले दो दशकों में अदालतों ने दहेज उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के दौरान यह पाया कि प्रति से मनुकुल के बाद बदला लेने की नीयत से भी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार तथा विवाह संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिशा में कानून तो अपना काम कर ही रहा है। परिवार और समाज को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा विवाह संस्था की पवित्रता बरकरार रहे। विवाह संस्था भी महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण का मजबूत मंच है। उसे और मजबूत करना समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस दिशा में नये सिरे से पहल की जरूरत है।



—प्रियंका सौरभ—

कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा में एकरूपता की नींव रखी और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने 14 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार किया। इस नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समानता में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम पेश किया और व्यावहारिक कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। इस योजना का उद्देश्य पोषण मानकों में सुधार करना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना था। एसएसए का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाना और लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को खत्म करना था। आरटीई अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बना दिया, जिससे सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित हुई। एनसीईआरटी 2005 का उद्देश्य सीखने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षा को वास्तविक को बढ़ावा देने के लिए अधिक



प्रसंगिक बनाया था। इसने रटने की आदत से हटकर परियोजना-आधारित सीखने और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया।

समय शिक्षा अभियान एकीकृत योजना का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को सुधार करना था। इसने हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा के लिए स्कूलों को अनुदान प्रदान किया। (पुनर्गठित) 2020 ने प्रारंभिक चयनन की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कक्षा 10 के बाद कठिन धाराओं को खत्म करने जैसे परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव रखा। यह समग्र विकास के उद्देश्य से शिक्षा के मार्गों में बहु-विषयक सीखने और लचीलेपन पर जोर देता है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सामने आने वाली चुनौतियाँ चुनौतियाँ क्षेत्रों में गुणवत्ता की असमानताएँ हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जहाँ कई ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी

ढाँचे और योग्य शिक्षकों की कमी है। एसईआर 2018 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 50-बच्चे ही बुनियादी पाठ पढ़ सकते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं को उजागर करता है। शिक्षा प्रणाली अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे छात्र काथ्यल रूप में आवश्यक व्यावहारिक नौकरी कौशल के लिए तैयार नहीं होते हैं। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री वाले स्नातकों में अक्सर नौकरी-विशिष्ट कौशल की कमी होती है, जिससे उच्च बेरोजगारी दर होती है। प्रणाली अभी भी रटने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सीमित आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमताएँ होती हैं। आईसीएस और सीपीएसई में परीक्षाएं अनुपयोगी-आधारित सीखने के बजाय सामग्री को याद करने पर केंद्रित होती हैं, जिससे रचनात्मक सोच में बढ़ावा नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमियाँ शिक्षकों को प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो शिक्षण की

गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को पर्याप्त रूप से सम्बोधित करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की आलोचना की गई है। डिजिटल शिक्षा के विकास के बावजूद, तकनीकी बुनियादी ढांचा अपर्याप्त बना हुआ है, खासकर ग्रामीण और दूरदर्ज क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच और डिवाइस की पहुँच अभी भी कम है, जिससे छात्रों का आधुनिक शैक्षिक उपकरणों से संपर्क सीमित हो जाता है।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता वास्तविक दुनिया के कौशल के साथ संरेखण की मांग करती है। आमूलचूल परिवर्तन छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, शिक्षा को वास्तविक दुनिया की मांगों के साथ संरेखित कर सकता है।

फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक कौशल और हाथों से सीखने पर जोर देती है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों की अधिक सहभागिता और रोजगार क्षमता होती है। आमूलचूल सुधार लचीले शिक्षा मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर अलग-अलग सीखने के मार्ग अपनाने की अनुमति मिलती है। जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा के बीच संतुलन प्रदान करती है, जिससे रोजगार क्षमता में सुधार होता है। अतिरिक्त छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण ने संसाधनों से छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और आलोचनात्मक तर्क को बढ़ावा

दिया है, जिससे छात्रों को पैदा करने में मदद मिलती है। स्कूलों में मिश्रित शिक्षा दूरदर्ज क्षेत्रों में छात्रों को आमने-सामने बातचीत से लाभान्वित करते हुए डिजिटल सामग्री तक पहुँचने की अनुमति देती है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग स्कूलों के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षण और संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में। ब्रिटिश काउन्सिल भारतीय राज्यों के साथ मिलकर शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार और वैश्विक शिक्षण मानकों को पेश करती है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर शिक्षण परिणाम मिलेंगे।

आमूलचूल परिवर्तन उच्च-दांव वाली परीक्षाओं से दूर जा सकता है और अधिक निरंतर मूल्यांकन विधियों को अपना सकता है, जिससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम हो सकता है। सिंगापूर ने छात्रों के प्रदर्शन को मापने, तनाव को कम करने और सीखने के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन रणनीतियों को लागू किया है। आमूलचूल परिवर्तन से पाठ्यक्रम में शैक्षणिक-सांख्यिक शिक्षा को प्रभावी ढाँचे-सांख्यिक शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, जिससे पहुँच और सहभागिता बढ़ सकती है। कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करने से पारंपरिक सुधारों से परे अभिनव समाधान। शुरुआती चरण में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा शुरू करने से छात्रों को व्यावहारिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा, जिससे वे कार्यबल के लिए तैयार होंगे।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता है। फिनलैंड के छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण और दक्षिण कोशिका के व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए एन 2020 के दृष्टिकोण के साथ मिलकर समावेशी और डिजिटल शैक्षिक परिणाम प्राप्त कर सकता है।

राजकपूर: नीली आंखों का वो रंगीन जादू

—हेमंत पाल—

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्ममेकर रहे राज कपूर ने हिफ़्दी सिनेमा को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि विश्व सिनेमा पर भी अमिट छाप छोड़ी। द ग्रेटेस्ट शोमैन नाम से मशहूर इस स्वर्णली नीली आंखों वाले बहुमुखी कलाकार ने फिल्म मेंकिंग, एक्टिंग और निर्देशन में ऐसा काम किया, जो आज भी प्रेरक है। उनकी जन्मशती के मौके पर आरके फिल्म, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और एनएफडीसी साथ मिलकर खास उत्सव मना रहे हैं। इसमें उनकी 10 चुनिंदा फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ और 1988 में निधन हो गया था। आज वे होते तो 100 साल के होते। सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर के बारे में जिन्हें लाता था कि उनके बाद हिंदी फिल्मों का शो थम जाएगा, वे कहीं नहीं कलत वहे हैं। लेकिन, यदि वे आज जीवित होते, तो देखते कि फिल्म प्रसासक उनकी सी वी जयदी मना रहे हैं। 'मेरा नाम जोकर' में उन्होंने सच कहा था 'कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में सितारे रहेंगे सदा और जाइएगा नहीं शो अभी खत्म नहीं हुआ।' अब लगने लगा कि राज कपूर ने खेल खेले ही हैं, ही. लेकिन सच ही कहा था कि शो अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर आरके फिल्म, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और एनएफडीसी एक साथ मिलकर एक खास उत्सव मना रहे हैं। इसमें 40 शहरों के 135 सिनेमाघरों में राज कपूर की 10 फिल्में प्रदर्शित हो रही हैं। राज कपूर 100 शो सेंसिटीवेटिड द सेंसटिव ऑफ द ग्रेटेस्ट शोमैन नाम का बह उत्सव 13 दिसंबर तक चला। और 15 दिसंबर तक चला। इस दौरान उनकी फिल्में की स्क्रीनिंग फैडीआर-आईनॉस और सिनेमासिंस सिनेमाघरों में हो रही है जिसमें आग, वरसत, आवाज़, रंग बरती है, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और 'राम तेरे गंगा मेला' का प्रदर्शन किया जा रहा है।

राज कपूर के बड़े रणधीर कपूर ने कहा भी है कि राज कपूर फिल्में फिल्ममेकर नहीं, दूरदर्शी हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा की भावनात्मक परंपरा को आकार दिया। उनकी कलाशियाँ केवल फिल्में नहीं, बल्कि भावनात्मक यात्राएँ हैं, जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं। यह उत्सव उनके नजरिये की



हमारी छोटी सी श्रद्धांजलि है। उनके पते रणधीर कपूर ने कहा कि हमें गाँव बहती है। प्रणाली अभी भी रटने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सीमित आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमताएँ होती हैं। आईसीएस और सीपीएसई में परीक्षाएँ अनुपयोगी-आधारित सीखने के बजाय सामग्री को याद करने पर केंद्रित होती हैं, जिससे रचनात्मक सोच में बढ़ावा नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमियाँ शिक्षकों को प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो शिक्षण की

सोवियत संघ में भी एक मशहूर हस्ती थे।

उनकी सबसे बड़ी सफलता और खासियत थी उनके काम करने का उम्दा स्टायल। मसलन जिस देश में गंगा बहती है की कहानी सुनने के बाद शंकर जयकिशन ने यह कहा कि बेहतर होगा वह इसका संगीत किसी दूसरे संगीतकार को दें, क्योंकि इसमें गाँवों की सिमसुगंध ही नहीं है। इसी स्थानांक में राज कपूर ने सात दिन में यारह गाँवों की सिमसुगंध निकालकर सभी को अचमित कर दिया। कहा जाता है कि वह अपनी फिल्मों के संगीत को हस्तियों से पास करवाकर कथाकार का दिलसा बनाते थे। उनकी फिल्मों में आम आदमी के सपने, गाँव और शहर के बीच का संघर्ष और भावनात्मक कहानियाँ जीवित हो उठती थीं।

राज कपूर का जन्म पठानी हिन्दू परिवार में हुआ था। पाँच भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े राज कपूर ने अपनी फिल्मों से जेम्सबॉय कॉर्नेलियस स्कूल, कोलाकात और कर्नल ब्राउन की शिक्षा स्कूल देहरादून में ली। बाद में 1930 के दशक में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में क्लेयर-बॉय और पुष्पी थियटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया, ये दोनों कम्पनियाँ उनके पिता पुष्पीराज कपूर की थीं। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में इंग्लैन्ड (1935) और हमारी बात (1943), गीरी (1943) में छोटी भूमिकाएँ कीं। फिर फिल्म वाल्मीकि (1946), नाद और अमंगम (1948) में कृष्ण की भूमिका निभाई जो 'उत्तमा इन्द्राय' की ख्य निताता-निर्देशक बनकर फिल्म निर्माण करें। उसका सनना 24 साल की उम्र में फिल्म आग (1948) के साथ पूरा हुआ। जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, निर्माण और निर्देशन भी स्वयं किया था। इसके बाद बेमरु में 1950 में अपने आरके स्टुडियो की स्थापना की और 1951 में 'आवारा' में कमाना नायक के रूप में ख्याति पाई।

—डॉ. शशांक द्विवेदी—

पिछले लगभग दो साल से यूक्रेन-रूस युद्ध जारी है। इस्राइल का हमला (फलस्तीन) 77 ईस्वी हिज्रुल्ला के बीच भी संघर्ष चल रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में शांति का दौर जारी है। इन युद्ध और संघर्षों के कारण से अभी भी यूरोप बिजली, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया महंगाई और ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। भारत तो अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से भी अधिक कच्चा तेल अन्ध देशों से आयात करता है।

भारत काफी सालों से अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करता जा रहा है। पिछले दिनों एक बड़ी उपलब्धि। हालिसलते हुए भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 10 अक्टूबर तक 200 गीगावॉट के आंकड़े को पार कर गई है। यह उपलब्धि ईसापूर्व की खास है कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावॉट है, जिसमें लगभग आठ हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हो गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार अक्षय ऊर्जा थियटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया, ये दोनों कम्पनियाँ उनके पिता पुष्पीराज कपूर की थीं। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में इंग्लैन्ड (1935) और हमारी बात (1943), गीरी (1943) में छोटी भूमिकाएँ कीं। फिर फिल्म वाल्मीकि (1946), नाद और अमंगम (1948) में कृष्ण की भूमिका निभाई जो 'उत्तमा इन्द्राय' की ख्य निताता-निर्देशक बनकर फिल्म निर्माण करें। उसका सनना 24 साल की उम्र में फिल्म आग (1948) के साथ पूरा हुआ। जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, निर्माण और निर्देशन भी स्वयं किया था। इसके बाद बेमरु में 1950 में अपने आरके स्टुडियो की स्थापना की और 1951 में 'आवारा' में कमाना नायक के रूप में ख्याति पाई।



बढ़ रही है। द्रुतगति से देश के विकास के लिए औद्योगीकरण, परिवहन और कृषि के लिए ऊर्जा की उच्च देना होगा। इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता है। देश में बिजली की मांग भी वर्तमान उत्पादकता से कहीं अधिक है। आवश्यकता को अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता है। कोविड महामारी का दुष्प्रभाव लगभग खत्म होने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है जिस कारण से बिजली की मांग भी बढ़ी है। आने वाले समय में भारत में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि भारत सहित दुनियाभर में अब ऊर्जा के गैर-अक्षय संसाधनों के मुक़ाबले अक्षय ऊर्जा संसाधनों की मांग निरंतर तेजी से बढ़ रही है।

ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। अपना भविष्य उज्ज्वल बनाए रखने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में सबसे तारक की ऊर्जा सृष्टि ईंधन बनकर अत्यंत आवश्यक है। आज हम बहुत करीब तो ही भविष्य सुनिश्चित कर पाएँगे। दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन, इस्पात, तेल, कोला, प्राकृतिक गैस इत्यादि ऊर्जा स्रोतों द्वारा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन की जा रही है, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में ऊर्जा सृष्टि इंधन की अत्यधिक कमी होने या इंधन समाप्त होने का भय पैदा हो गया है।

वस्तुतः ऊर्जा हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। मौज्जा, प्रकाश, यातायात, आवास, स्वास्थ्य की पूर्ण आवश्यकताओं के साथ नवीकरणीय, दूरसंचार, सूक्ष्म संसाधन, पेटेंट जैसी आवश्यकताओं में भी ऊर्जा के विभिन्न रूपों ने हमारी जीववैज्ञानिक अनिवार्य बना लिया है। इन सबमें भी बिजली ऊर्जा वह प्रकार है जो सबसे

सुगमता से हर कहीं सदैव हमारी सुविधा हेतु सुलभ है। यही कारण है कि अन्य ऊर्जा विकल्पों को बिजली में बदलकर ही उपयोग किया जाता है। वास्तव में यदि ऊर्जा का उपयोग स्रोत-सम्पन्न कर नहीं किया गया तो इसका भंडार जल्द ही समाप्त हो सकता है। प्रकृति पर जितना अधिक हमारा हाथ है, उतना ही हमारी भावी पीढ़ियों का भी है। जब हम अपने पूर्वजों द्वारा लगाए हुए वृक्षों के फल खाते हैं, उनकी संतानों व रोहबर का उपयोग करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भविष्य के लिए भी नैतिक संस्मरणों को सुनिश्चित छोड़ें और, कम से कम अपने निहित स्वार्थों के लिए उनका दुरुपयोग न करें, अन्यथा भावी पीढ़ी और प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी।

आज भारत 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' का समस्त नेतृत्व कर रहा है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों और भविष्य में इसके समाप्त होने के भय का समाधान ही हमारे लिए ही निहित है। हालाँकि, नवीकरणीय ऊर्जा में संचारालमक प्रगति के बावजूद भारत की जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता 'नेट जीरो' के लक्ष्य में बाधक बन सकती है। 'पंचायत सौभाग्य' के तहत केंद्र सरकार सीओपी-26 समझौते में घोषित कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करके, 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक ले जाने, अपनी कुल जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करने तथा 2070 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रतिबद्धता से जुटी है।—लेखक विज्ञान विषयों के

है। यह सच है। कुछ समय बाद वाक्य मोहावेल सती आफ हो गया था। मामले की छानबीन हो चुकी थी। जीआरपी को सीटी टीवी फुटज में जानकारी मिली है कि बुधवार को शाम पांच बजे के करीब विश्वक अखिलेश मिश्र देवरिया नरेश रंजने स्टेशन के पार्किंग छोर पर मस्ती हाड़ के तर्फ से आए। लैपटॉप में नमूना पर बाद फुट आवर बिज के समय उदरती किया। उस समय फुटफॉर्म पर आरपीएफ स्टप्स ने विश्वक को यानी समेत पर दृष्टा तो अखिलेश ने चले जाइ। साहब हम टीसी है, चले जाएंगे। आरपीएफ जवान उन्हें मुने छोदी की बात कह कर आए निकल गया। मुह छोदी के बाद विश्वक प्रतीतालय में पहुंचे। सीटी टीवी फुटज में बाद अकेले जाने हुए दिख रहे हैं। इसके बाद वह प्रतिकल्प में ब्रेक फ्रेम पर उते गए। लाभांग सता बाद के लगभग एक यात्री ने प्रतीतालय में यात्री की मोत की सूचना स्टेशन पर तैनात टीसी को दिया। टीसी ने इसकी जानकारी को टीआरपी और आरपीएफ को दिया। आरपीएफ ने रंजने के विश्वकत्स को बुलाया उन्होंने जाले बाद भंडिक कोलेंज भंग किया, जहां विश्वकत्स ने उन्हें नु पौचित कर दिया था। अखिलेश मिश्र के पाकें से सुरसहजद नुत मिलने की चर्चा जेरेण पर है। शिक्को का कर्ना

प्रेमी युगल ने छप्पर की बड़ेर से लटककर दी जान

न्यायालय प्रारूपण
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज
(रुजिडो) मोहोदय बस्ती जिला—बस्ती
प्रकीर्णवाद सं. 64/2024
शकुन्तला देवी
बनान
अंम प्रकाश आदि
1. अंम प्रकाश उम्र 48 साल 34
वर्षा विदुषा कुमार उम्र 44 साल पुत्रगण
रमजुआल साहिल रमजुआर तथा
ऊजी परमान नगर पश्चिम तहसील
हजारी जिला—बस्ती
तारीख पेशी 14-02-2025
बुकि उपरनिर्माणित ने
इस न्यायालय में आवेदन किया है
कि अतएव आदेश एतद द्वारा
घोषनीवी हो जाति है कि आज इसे
अदालत के खिलाफ हेतु सन्दर्भित
करने के लिये 2025 के माह 02
के 14 दिवस को 10.00 बजे पूर्वानु
में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुदिष्ट
अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो
और ईसा न करने पर उक्त आवेदन
एक पक्षीय रूप से सुन जायगा।
मेरे हुताक्षर और
न्यायालय को सहित आज 20
के माह के दिवस को
निकाली जाय।
दो हाकिम